>

Title: Presentation of the 58th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Gratns (2013-14) of the Ministry of Law and Justice.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के अठावनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(*Interruptions*)